

अरबपति एलन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी बनाई

उन्होंने कहा कि नई पार्टी का मकसद अमेरिका में दो दलीय राजनीति को चुनौती देना है

लॉस एंजिल्स, 06 जुलाई। मशहूर अरबपति एलन मस्क ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से विवाद के कुछ हफ्तों बाद एलन मस्क ने यह घोषणा की है।

एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने “अमेरिका पार्टी” बनाई है। इसका मकसद अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की दो-दलीय राजनीति को चुनौती देना होगा।

एलन मस्क ने कहा, अमेरिका पार्टी आपको आपकी स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। सप्ताह की शुरुआत में एलन मस्क ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया था जिसमें लोगों ने जबर्दस्त भागीदारी करते हुए एक नई राजनीतिक ताकत के लिए मजबूत समर्थन दिखाया था।

एलन मस्क ने शुक्रवार चार जुलाई को इस सर्वेक्षण की घोषणा करते हुए लिखा, स्वतंत्रता दिवस यह पृष्ठने का

■ **मस्क ने कहा कि एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में 12 लाख उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिशत ने कहा था कि वे दो-दलीय प्रणाली से स्वतंत्रता चाहते हैं।**

■ **एलन मस्क ने कहा कि उनकी “अमेरिका पार्टी” प्रारंभ में दो या तीन सीनेट सीटों व 8 से 10 गृह जिलों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।**

सही समय है कि क्या आप दो- दलीय प्रणाली से स्वतंत्रता चाहते हैं। लगभग 12 लाख उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिशत से अधिक ने इस विचार का समर्थन किया।

मस्क ने शनिवार को इसके परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए, लिखा आप एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं और आपको यह मिल जाएगा! जब हमारे देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार से दिवालिया बनाने की बात आती है, तो हम एक-पक्षीय प्रणाली में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं।

एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका

पार्टी दो या तीन सीनेट सीटों और आठ से 10 गृह जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस रणनीति का मकसद कांग्रेस में नियंत्रण हासिल करना है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इसे चुनाव आयोग में औपचारिक तौर पर पंजीकृत कराया गया है और फिलहाल इसकी कमान किसके हाथों में रहेगी।

इस बीच चुनाव-कानून विशेषज्ञों ने नई पार्टियों की राह में आने वाली अड़चनों का भी जिक्र किया है। कैलिफ़ोर्निया में, आयोगकों को या तो लगभग 75,000 सदस्यों को पंजीकृत

करना होगा या मतपत्रों पर अपनी पार्टी की उपस्थिति के लिए 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र को दर्शाना होगा।

राजनीतिक रणनीतिकारों का सुझाव है कि मस्क की इस घोषणा का उद्देश्य राजनीति में एक टिकाऊ तीसरे विकल्प का निर्माण करने की बजाए सांसदों पर दबाव डालना अधिक प्रतीत होता है। यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पारित होने के बाद उठाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन में कटौती की गई है और संघीय खर्च में वृद्धि की गई है। इन उपायों का विरोध एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने किया है क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूडि से लाभ उठाती रही है।

विश्लेषकों का कहना है कि मस्क का यह कदम अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के बजाए एक सोची समझी रणनीति के तहत सौदेबाजी अधिक दिखाई पड़ता है।

ब्राजील में मोदी का भव्य स्वागत हुआ

रियो डी जेनेरियो/ नयी दिल्ली, 06 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में शनिवार देर रात अर्जेन्टीना से ब्राजील पहुंचे, जहां वे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

रियो डी जेनेरो हवाई अड्डे पर मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में उतरा, जहां मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और बाद में राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लुला दा सिल्वा के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए

■ **ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने रियो डी जेनेरो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया।**

उनकी राजधानी ब्रासीलिया जाऊंगा। इस यात्रा के दौरान बैठकों और बात-चीत के सार्थक दौर की उम्मीद है। भारतीय समुदाय के शानदार स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा , ब्राजील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रियो डी जेनेरो में बहुत ही शानदार स्वागत किया। यह आश्चर्यजनक है कि वे भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के लिए कितने लालायित हैं। मोदी ने अपनी पोस्ट में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह की कुछ झलकियाँ भी साझा की हैं।

नवम्बर 24 में रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अधिकारिक बंगला खाली नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर बंगला खाली कराने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 6 जुलाई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ का सरकारी बंगले में ज्यादा दिन तक रुकना अब विवाद का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 5, कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला तुरंत खाली करवाया जाए। यह बंगला देश के मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक निवास है। चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में रिटायर हुए थे, लेकिन अब तक वही रह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जुलाई को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ तय समय से ज्यादा दिन बंगले में रह

रहे हैं। नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पूर्व मुख्य न्यायधीश छह महीने तक टाइप-सात बंगले में रह सकते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ टाइप-आठ बंगले में आठ महीने से रह रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

इस मुद्दे पर चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देरी उनके पारिवारिक कारणों की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियाँ को विशेष देखभाल की जरूरत है और उनके लिए उपयुक्त घर ढूँढ़ना आसान नहीं था। सरकार ने उन्हें किराए पर दूसरा घर दिया है, जिसकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत पूरी होते ही वह शिफ्ट हो जाएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद दो मुख्य

■ **पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी दो बेटियों को विशेष देखभाल की जरूरत है। सरकार ने किराये पर दूसरा मकान दिया है, जिसकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत पूरी होते ही शिफ्ट हो जाऊंगा।**

न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला लेने

से इन्कार कर दिया। दोनों ने अपने पुराने आवास में ही रहना पसंद किया। इसी वजह से चंद्रचूड़ को बंगले में अतिरिक्त समय मिलने में आसानी हुई।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंद्रचूड़ को पहले ही अप्रैल 2025 तक बंगला रखने की अनुमति दी गई थी। बाद में मई 2025 तक मौखिक रूप से मोहलत भी मिली। लेकिन अब वह समय भी बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता क्योंकि कई जजों को आवास की जरूरत है।

चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कुछ ही दिनों

में बंगला छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को भी परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त समय दिया गया है। वह यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के साथ पहले ही साझा कर चुके हैं।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा कम ही देखा गया है जब अदालत को अपने आधिकारिक निवास को खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को लिखित रूप से कहना पड़े। आमतौर पर ऐसे मामलों में अंदरखाने समाधान निकाल लिया जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में अदालत को सख्त कदम उठाना पड़ा, जिससे यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है।

आरजेडी ने बिहार वोटर लिस्ट रिविज़न को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

विपक्ष के महागठबंधन ने इस मामले में 9 जुलाई को बिहार में चक्काजाम का एलान किया

■ **सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले के चलते बिहार के लाखों लोगों का मतदान का अधिकार छिन जायेगा।**

पटना, 06 जुलाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग पर और इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। महागठबंधन ने इस मामले को लेकर 9 जुलाई को चक्का जाम का एलान भी किया है।

हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए जरूरी है।

दूसरी ओर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आरजेडी सांसद डॉ. मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस कदम को चुनौती दी है और चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

इससे पहले एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और टीएमसी सांसद महुआ मोइजा भी चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इसके चलते बिहार के

लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार छीन जाएगा।

बिहार में इसी साल चुनाव होना है। बीते 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) की घोषणा की थी। आयोग के इस फैसले पर कई विपक्षी दल के नेता भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

इस मामले में चुनाव सुधारों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संस्था का कहना है कि, चुनाव आयोग की यह नीति संविधान के खिलाफ है। इससे वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अवैध बंगलादेशियों को वापस भेजने के लिये त्रिपुरा से दिल्ली पैदल मार्च

अगरतला, 06 जुलाई। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए सरकार की सहयोगी पार्टी टीआईपीआरए मोथा, ने 1971 के बाद यहां आकर "जाली" दस्तावेजों के साथ यहां रह रहे अवैध बंगलादेशी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने की मांग को लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया है। टीआईपीआरए मोथा नेताओं के एक समूह ने शहर के उत्तरी द्वार से अपना मार्च शुरू किया जो दिल्ली के जंतर मंतर पर

■ **मार्च का नेतृत्व कर रहे डेविड मुरासिंह ने कहा कि बंगलादेशी घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय समस्या है।**

समाप्त होगा। टीआईपीआरए मोथा को उम्मीद है कि इस मार्च के जरिये जनता को जागरूक किया जा सकेगा। यह मार्च कई राज्यों और शहरों से गुजरेगा और अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा।

दल का नेतृत्व कर रहे टीआईपीआरए मोथा नेता डेविड मुरासिंह ने कहा, बंगलादेशी घुसपैठ एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इसे हल करने में त्रिपुरा सरकार की भूमिका प्रभावी नहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था गुंजी बेस कैंप पहुंचा

नैनीताल, 06 जून। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रविवार को सकुशल सीमांत गुंजी पहुंच गया है।

पिथौरागढ़ के धारचूला के उप जिलाधिकारी जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि यह जत्था आज धारचूला से चल कर पहले आधार शिविर गुंजी पहुंच गया है। गुंजी में श्रद्धालुओं का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।

उन्होंने बताया कि आज सुबह धारचूला तवाघाट मार्ग पर भारी भूस्खलन के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित हो गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और जिला प्रशासन की टीम

■ **गुंजी में श्रद्धालुओं का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।**

तत्काल मौके पर पहुंची और दोपहर तक मार्ग को पूरी तरह से चालू कर दिया गया इससे कैलाश यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।

वहीं दूसरी ओर कैलाश यात्रियों का जत्था आज धारचूला में रंग संग्रहालय पहुंचने पर रंग महिलाओं ने पारम्परिक वेशभूषा में स्वागत किया। कैलाश यात्रियों को रं संस्कृति की जानकारी दी। कैलाश यात्रियों के दल ने रंग संग्रहालय की 10,000 की राशि भेंट स्वरूप दी।